

कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने बीमा एजेंटों को इस शर्त को बताने से रोक दिया जिसके कारण हवाई कोनों का नुकसान हुआ। यह शर्त पूर्व सरकार के समय में बतली गई थी और हो सकता है कि सरकार ने जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला हो कि वे इस तरह के आरोपों को एजेंटों को न बतलाने को कहें, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के अधिकारियों पर ऐसा दबाव तो नहीं डाला है और यदि हमारी सरकार ने ऐसे आरोप नही दिये हैं तो क्या सरकार उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपने एजेंटों को इस शर्त को न बताने के लिए कहा हो।

तीसरे क्या यह सही नहीं है कि जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और गलत समाचार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बीमा डेवलपमेंट अधिकारियों के नेता के खिलाफ कार्यवाही करेगी अगर यह खबर गलत हो?

(ii) REPORTED LEAKAGE OF ALVA COMMISSION REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur):

With your permission, I am raising this matter of urgent public importance under rule 377: the statement of Shri Raj Narain hon. Health Minister in the Lok Sabha on 2nd March 1978 that the report of the Alva Commission has come as a "shocking revelation" on the treatment meted out to Shri Jayaprakash Narain during his detention in the PGI and the news item in the Indian Express, March 4, 1978 'PGI doctors indicated' is causing grave doubts among the people of the country about the PGI, Chandigarh. The entire nation was looking forward to see the real contents of the report which the hon. Minister promised to place on the Table of the House. But the subsequent decision of the Minister not to disclose the so-called 'interim report' to spread dissatisfaction and suspicious amongst the people. Now a news report from the Tribune,

Chandigarh dated 12-3-1978 under the heading of 'Mystery of JP's Digoxin Toxicity not solved' has disclosed really the shocking revelations which must be probed through a judicial enquiry to clear the doubts and suspicion. The demand for a judicial enquiry as put forth by PGI doctors has a general support from all walks of life and must be conceded to so that justice prevails and the public is made aware of the facts. Only in judicial enquiry the realities can be brought to book where everybody shall have the right to say and the right to defence. In view of the above, I would like to request the hon. Minister to make a categorical statement about the leakage of report to the Press before it is presented to the Parliament and I also strongly demand a judicial enquiry into the whole incident.

(ii) SITUATION IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) :

अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अज्ञानगढ़ी और गैरअज्ञानगढ़ी स्थिति से उत्पन्न अज्ञान और उपद्रवग्रस्त वातावरण की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

वहाँ के वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को दो भागों में विभक्त कर दिया है— एक तो अज्ञानगढ़ी और दूसरा गैरअज्ञानगढ़ी। अज्ञानगढ़ी से उनका मतलब यह है कि अलीगढ़ से पूर्व के जो भी विद्यार्थी हैं वे अज्ञानगढ़ी हैं। इस सम्बन्ध में वहाँ के एक विद्यार्थी, श्री अमजदबां जो कि सुलेमान हाल में रहते हैं, ने जब वाइस चांसलर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बताया कि अज्ञानगढ़ी भी अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से पूर्व और बिहार के बाहर तक का क्षेत्र। इस स्थिति के चलते वहाँ के विद्यार्थियों के संगठन ने, अध्यापक संगठन ने, कर्मचारियों के संगठन ने वहाँ के वाइस चांसलर को वहाँ से हटाने की मांग की है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि इस भ्रष्टाचार,

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

अनाचार और दुराचार के खिलाफ वहाँ एक जेहाद-ना छिड़ गया है। आजमगढ़ी और वीर आजमगढ़ी की तिकड़म करके वहाँ के वाइस चांसलर ने आजमगढ़ी लडको को पिटाया, जिसके कारण लडकों के सिर टूटे, पैर टूटे और हाथ टूटे। स्थिति बहुत भयकर बनती चली जा रही है। अलीगढ़ से पूर्व के जो बिग्राही हैं उन में से 28 को निष्कासन कर दिया गया है और यह निष्कासन बिना अनुशासन समिति की सिफारिश के किया गया है। यह हालत वहाँ बनती चली जा रही है। आज विश्वविद्यालय दो गुटों में पूरा का पूरा विभक्त हो चुका है। लखनऊ, आजमगढ़, बाराणसी, गोरखपुर, बस्ती यह सब तो आजमगढ़िया इलाका है, जो बिहार के बोर्डर से मटा हुआ है, यहाँ के लोग आजमगढ़ी इलाके के हैं और उनके साथ वहाँ का वाइस चांसलर सीतेला व्यवहार कर रहा है। इस तरह के व्यवहार के चलते वहाँ के विद्यार्थियों के लिए वहाँ रहना दुभार हो गया है। अस्त व्यस्त, जस्त, घोर आपदा अस्त और उपद्रवग्रस्त, ऐसी स्थिति में वहाँ वाइस चांसलर के रहते बनती चली जा रही है। स्थिति बंद से बदतर होती जा रही है। वहाँ विद्यार्थियों की मांग है कि वाइस चांसलर को तुरन्त हटाया जाए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस और ध्यान दे और तत्काल कोई प्रभावकारी कार्य करे।

(iv) LIKELIHOOD OF LOCUST INVASION

श्री माधू सिंह (बीसा) नियम 377 के तहत मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार अफ्रीका, अरब देशों और भारतीय उपमहाद्वीप में भारी टिड्डी दलों के हमले की आशंका उत्पन्न हो गई है। पता चला है कि अरबों की संख्या में टिड्डियों के दल अफ्रीकी देशों में प्रविष्ट हो रहे हैं। टिड्डियों की संख्या एक किलोमीटर में बालीस हजार लाख से से क आठ हजार लाख तक होती है। 1958 में

टिड्डियों के दल अरबों में हमारे वहाँ 1.67 लाख टन अनाज नष्ट कर दिया था।

स्वतन्त्रता के बाद चीन और पाकिस्तान ने ही हमारे देश पर हमला नहीं किया। कई बार इन टिड्डी दलों ने भी किया जिससे लाखों टन अनाज की क्षति हुई। इसके बारे में मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूँ, मंत्री महोदय को सतर्क करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि ये टिड्डी दल हमारे देश की सीमाओं में प्रविष्ट न हों मकें और उनके द्वारा नष्ट होने वाले अनाज को बचाया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश को ज प्रागे क्षति होगी उससे बचा नहीं जा सकेगा।

(v) SERIOUS SITUATION IN PATNA

श्री मनोहर लाल (कानपुर) 377 के अधीन मैं आपका तथा इस माननीय मदन का ध्यान दिलाने हुए पटना में जो विस्फोटक स्थिति पैदा होनी जा रही है उसकी ओर ध्यान खीचना चाहता हूँ। कांग्रेस ने शुभ से ही डिवाइड एंड रूल की नीति का अवलम्बन किया था। इस नीति का अवलम्बन करने में उसने 30 साल तक जरा भी सकोच नहीं किया। गद्दी से हटने के बाद भी वह खुलेआम इसी नीति पर चल रही है। आपने जैसा अखबारों में देखा होगा कि श्री जयप्रकाश नारायण के अमून महोत्सव पर भी जातिवाद का नाग लगाया गया और कुछ अशांतीय घटनाएँ की गईं। श्री जगजीवन राम के साथ वहाँ के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर के साथ भी इसी तरह का अशुभ व्यवहार किया गया है। अराजक तत्वों के साथ इन लोगों ने मिल कर इस तरह की घटनाएँ वहाँ पर कराई हैं। काका कालेसकर की अध्यक्षता में बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें बैंकवर्ड क्लॉसिस के लोगों के लिए तरह तरह की सुविधाएँ देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन आज तक हमारी कांग्रेस की सरकार ने जब तक यह सत्ता में रही इस रिपोर्ट को कार्यरूप में परिणत नहीं किया। आज जब जनता पार्टी की सरकार